'एजूकेशन हब' या शिक्षा का सत्यानाश

बीते शनिवार यानी 28 सितम्बर 2013 को अग्रवाल कॉलेज बल्लबगढ़ की छात्राओं ने परीक्षा परिणाम की गलतियों के विरोध में प्रदर्शन किया जिसे दैनिक अख़बारों ने 'फेल छात्राओं का हंगामा' कहकर छापा, जैसे कि यह छात्राओं की गलती हो! और पुलिस ने उनपर लाठी भांजकर अपना अंग्रेजों से विरासत में मिला कर्त्तव्य (गरीबों को पीटने का) पूरा किया तो कॉलेज ने तीन छात्राओं को सस्पेंड कर उनके ख़िलाफ़ और कार्रवाई तय करने के लिये एक कमेटी का गठन कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री की। शायद सिर्फ सस्पेंड करने भर से प्रिंसिपल कृष्ण कांत गुप्ता के पुरुषत्व की संतुष्टि नहीं हुई था। किसी ने उन छात्राओं के साथ हुये इस अन्याय को समझने और उसे दूर करने की कोशिश नहीं की। यह ठीक उसी तरह था जैसे आसाराम जैसे लोग बलात्कार के लिये उस लड़की को ही जिम्मेवार ठहरा रहे थे। आखिर हमारी पुलिस क्यों नहीं ऐसी घटनाओं की सूचना सरकार और सम्बंधित विभाग (यहां एम. डी. यूनिवर्सिटी) को भेजती? प्रिंसिपल क्यों नहीं सरकार और 'यू. जी. सी.' को यूनिवर्सिटी में हो रही इस 'फिरौती वसूली' के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिये लिखते? क्या ये पढ़ने वाले बच्चे हमारे अपने नहीं है? क्या ये हमारे दुश्मन है? यदि नहीं तो फ़िर उनके साथ ऐसा दुश्मनीपूर्ण व्यवहार क्यों किया गया?

घटना को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है कि इससे पहले ऐसी ही घटनाएं जिले के चार कॉलेजों में और हो चुकी हैं। उनमें भी इसी तरह मेधावी छात्र-छात्राओं को थोक में जीरो नम्बर देकर फ़ेल कर दिया गया था और जब इन विद्यार्थियों ने एम.डी. यूनिवर्सिटी में विरोध पत्र भेजा तो वे सभी अच्छे अंकों में पास कर दिये गये। सबसे शर्मनाक वाकया तो यह पता चला है कि सैक्टर 16 ए फ़रीदाबाद की राजकीय महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल शोभा चुघ ने तो 500 रुपये प्रति छात्रा, यूनिवर्सिटी में रिश्वत देकर रिजल्ट ठीक करवाने के नाम पर, वसूल भी कर लिये थे। यह ढाई लाख रुपया इस 'बेचारी गरीब' प्रिंसिपल को तब वापिस करने पड़े जब बात खुल गई क्योंकि कई छात्राएं यूनिवर्सिटी से खुद ही अपना रिजल्ट ठीक करवा लायीं जबकि प्रिंसिपल को पैसे देने वाली अनेकों छात्राओं का रिजल्ट फ़िर भी ठीक नहीं हुआ।

ठीक यही घटना के एल मेहता दयानंद कॉलेज व डी.ए.वी शताब्दी कॉलेज फ़रीदाबाद में भी हो चुकी है। इसके अलावा फ़रीदाबाद के बाहर से भी ऐसी घटनाओं की सूचना है। इन सभी में ज़्यादातर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में यूनिवर्सिटी को दुरुस्त करने पड़े। शायद इस बीच वहां के क्लर्क काफ़ी फ़िरौती वसूल चुके होंगे-शोभा चुघ जैसी प्रिंसिपलों की बदौलत।

इसी तरह की एक और समस्या जो कॉलेजों में विकराल रूप धारण कर चुकी है वह है शिक्षकों की कमी। हर कॉलेज में शिक्षकों की अनेकों पोस्ट खाली पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अधिकतर कॉलेजों में तीन चौथाई तक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। पूरे हरियाणा में एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग ढ़ाई हज़ार प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में हमारे कॉलेजों में क्या पढ़ाई हो रही होगी यह आप समझ ही सकते हैं। इनमें से कुछ रिक्त पदों पर 'गेस्ट' और 'विजिटिंग प्रोफ़ेसरों' के नाम पर दिहाड़ीदार मज़दूर की तरह प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया है। और उनका शोषण भी उन्ही की तरह, बल्कि उनसे ज़्यादा किया जाता है।

इनमें 'गेस्ट प्रोफ़ेसर' को सबसे ज़्यादा 22 हज़ार रुपया प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि उनके समकक्ष नियमित प्राध्यापक 80 हज़ार से लेकर सवा लाख रुपया तक वेतन लेते हैं। ये नियमित प्राध्यापक अपने साथी उस गेस्ट प्रोफ़ेसर का उसी तरह शोषण करते हैं जैसे एक ठेकेदार एक मज़दूर का करता है। ये उन्हें अपने साथ स्टाफ़ रूम में बैठने तक में एतराज करते हैं। सभी तरह के रिजल्ट, रिर्पोटों आदि के काम उन्हीं से करवाये जाते हैं।

तीसरी जमात जो विजिटिंग प्रोफ़ेसरों की है। उनको अधिकतम 18000 रुपया तक मिलते हैं जबकि ज़्यादातर उनकी महीने की पगार आठ से नौ हज़ार रुपये तक पहुंचती है जो एक अनपढ़ दिहाड़ीदार मज़दूर से भी कम है। समझ सकते हैं कि कॉलेज का पुराना चपरासी जो आज पच्चीस से तीस हज़ार रुपये मासिक वेतन ले रहा होगा वह इनकी कितनी इज्जत करता होगा। और इस भयंकर शोषण और अन्याय में जी रहे इन प्रोफ़ेसरों के मन की व्यथा को कौन जानता है। क्यों नहीं सरकार नियमित प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति करती?

इस बारे में सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि सरकार ने तो तकरीबन 1700 पदों पर भरती के लिये 'हरियाणा लोक सेवा आयोग' को लिखा हुआ है। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी आयोग ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जानकार बताते हैं कि आयोग इसमें इसलिये रुचि नहीं ले रहा क्योंकि मेहनत ज़्यादा और कमाई कम है। इसलिये वह इन्जीनियरों, एच सी एस, पुलिस जैसी कम मेहनत लेकिन ज़्यादा 'माल' देने वाली पोस्टों के सेलेक्शन में जुटा है।

उच्च शिक्षा का सत्यानाश करने में इसी विभाग के 'डायरेक्टर जनरल' (इस पोस्ट का ये नाम शायद इन्होंने फ़ौज में जनरल बनने की अपनी अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिये करवाया है। वैसे ये प्राध्यापकों से व्यवहार भी इसी तरह करते है जैसे ये फ़ौज के जनरल हो और वे तुच्छ सिपाही!) अंकुर गुप्ता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने एक तुगलकी फ़रमान जारी कर अनेकों प्राध्यापकों की तैनाती दो-दो कॉलेजों में कर दी है। यानी तीन दिन वे एक कॉलेज में पढ़ायेंगे और तीन दिन दूसरे में। जब तक इस कॉलेज से तारतम्य बनाते हैं तब तक दूसरे कॉलेज में जाने का नम्बर आ जाता है और दूसरे कॉलेज में जाकर याद करते हैं कि किस-किस क्लास में पिछली बार क्या पढ़ाया था तब तक वहां से जाने का नम्बर आ जाता है। न वहां का सिलेबस पूरा हो पाता न यहां का। न उस कॉलेज की कोई जिम्मेवारी प्राध्यापक की न इस कॉलेज की।

बस प्राध्यापक तो धोबी के कुत्ते की तरह घर और घाट का चक्कर काटता रहता है इस कॉलेज से उस कॉलेज। और छात्र हैं कि ना उस कॉलेज के पढ़ पाते हैं ना इस कॉलेज के। अब इन मोहम्मद तुगलक अंकुर गुप्ता को कौन समझाये कि ये उनके दफ़्तर की फ़ाइलें नहीं हैं कि नीचे से सब लिखा आया और आपने बस साइन कर दिया, ये पढ़ाई है इसमें पढ़ाने के लिये पढ़कर भी जाना पड़ता है और बच्चों की अकादमिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन ग्रामीण क्षेत्र से है और कौन शहरी, कौन कैसे उदाहरण समझ पायेगा। और यूनिवर्सिटी के हाजिरी और अन्दरूनी नम्बरों के नियम की पालना कैसे होगी। क्योंकि जब दोनों कॉलेजों में आधा-आधा समय दिया है तो छात्रों की हाजिरी भी कम रहेगी और प्राध्यापक द्वारा दिये जाने वाले अंक भी आधे में से होंगे। इसमें दोनों कॉलेजों के छात्रों का फ़ेल होना तय है।

ऐसे ही किसी तुगलकी या भ्रष्ट दिमाग की उपज कॉलेजों में लागू 'एजूसेट' कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत हर कॉलेज में एक कमरा इसके लिये विशेष रूप से रखा गया है जिसमें बड़े परदे पर सैटेलाइट के जरिये चण्डीगढ़ से लेक्चर दिया जाता है। जिस कॉलेज में क्लास लेने के लिये कोई कमरा उपलब्ध न हो और कक्षायें पेड़ के नीचे लेनी पड़ती हों उसमें एक कमरा सिर्फ एजूसेट के लिये खाली रखना कितनी बड़ी विलासिता या फ़िजूलखर्ची है ये समझा जा सकता है। और जब हज़ारों पद शिक्षकों के रिक्त हों वहां एक शिक्षक को रोज़ाना चण्डीगढ़ के लिये मुक्त करना कितनी बड़ी मूर्खता है ये भी समझा जा सकता है। लेकिन जिनको ऐसी ही स्कीमें बनाकर उसमें कमीशन खाना हो और फ़िर उसे अपनी और सरकार की उपलब्धि बताकर वाहवाही लूटनी हो उन भ्रष्ट और ठगों के आगे पूरा शिक्षक और छात्र समाज बेबस है।

इसके अलावा कॉलेजों में पीने के पानी, शौचालय न होने की समस्या आम है। क्लर्कों की भयंकर कमी है। प्राध्यापकों को रेड क्रास, महिला सेल, एन.एस.एस. आदि जैसे दिखावटी और ऊपर वालों के लिये कमाऊ कामों में पिदाये रखा जाता है जबकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा होता है। इसके अलावा हर प्राध्यापक को हर छोटे-मोटे काम के लिये चंडीगढ़ भागना पड़ता है व वहां के भ्रष्टाचार को झेलना पड़ता है वह अलग है। मुख्यमंत्री को हरियाणा को 'एजूकेशन हब' बताकर अपनी बगले बजाने के बज़ाय, शिक्षा के इस सत्यानाश की तरफ़ ध्यान देना चाहिए वरना अगले साल चुनाव में जनता उनको जूते मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

-अजातशत्रु

जेलों में मोबाइल :जैमर नहीं सख्ती चाहिये

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले दिनों स्थानीय जेल की तलाशी में कई मोबाइल फ़ोन मिले थे। एक कैदी ने तो बाकायदा न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी पर बयान दिया कि उसने मोबाइल रखने के एवज में 10 000 रुपया मासिक जब जेल वालों को नहीं दिया तो उसकी कमर को जगह-जगह से लोहे की गर्म मुहर से दाग दिया था। इस सब के बावजूद 6 अक्टूबर को गुड़गांव की भोंडसी जेल से 36 मोबाइल का मिलना सिद्ध करता है कि जेल अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

आजकल देश की शायद ही कोई जेल ऐसी होगी जिसमें कैदियों के पास मोबाइल फ़ोन न हों। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि हर कैदी के पास मोबाइल होते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं साधन सम्पन्न कैदियों के लिये है जो इसके एवज में जेलरों को वाजिब रिश्वत दे सकते हैं। प्राय: शातिर अपराधी गिरोहों के लोग इस सुविधा के द्वारा जेल से ही अपना नेटवर्क बड़े मजे से चलाते रहते हैं। इससे समाज में अपराध व पुलिस के लिये सरदर्दी बढती है।

गुड़गांव पुलिस ने भी जेल पर तभी छापा मारा जब उसे काफ़ी मात्रा में ये शिकायतें मिलीं कि जेल में बंद कैदी लोगों को फ़ोन पर धमकियां दे रहे हैं।

समस्या से निपटने के लिये सरकार जेलों के आस-पास जैमर लगा रही है जिससे मोबाइल फ़ोन काम ही न कर सकें। अनेकों जगह ये लग भी चुके हैं। लेकिन समस्या का यह कोई समाधान नहीं है। जो लोग जेल में फ़ोन रख सकते हैं वे जैमरों को भी नाकाम कर सकते हैं। इसका एक मात्र हल यही है कि जिस जेल में मोबाइल मिले उस जेल के अधीक्षक तथा उसके सहायकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी जेल भेज दिया जाय। यह किसी से छिपा नहीं है कि जेल में उनकी मर्ज़ी के बिना एक सूई भी नहीं जा सकती। केवल मोबाइल के लिये नहीं जेल में हर काम व सुख-सुविधा पाने की अच्छी खासी 'फ़ीस' होती है। इससे जेल अधिकारियों को लाखों रुपये मासिक की आमदनी होती है जिसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है।

पलवल : न विकास न कानून व्यवस्था

पलवल (म.मो.)। सन 2008 में हुड्डा सरकार ने वोटों के गणित को देखकर पलवल को जिला बना कर यहाँ के लोगो को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए थे कि यहाँ की जनता को उनके दरवाजे पर न्याय मिला करेगा तथा यहाँ की कानून व्यवस्था चौक चौबंद होगी क्योंकि डी सी व एसपी समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी यहीं बैठा करेंगे। लेकिन बजाए व्यवस्था सुधार के यहाँ तो कानून व व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है।

डीसी हो एसपी किसी के यहाँ तैनात रहने से बजाय लाभ के उलटा यहाँ की जनता को पिछले पांच साल में नुक्सान अधिक झेलना पड़ा है। जिला बनने से पहले जिला स्तर के अधिकारी फरीदाबाद बैठते थे जो कुछ काम तो अपने पद की गरिमा के अनुरूप कर ही देते थे लेकिन यहाँ पहले तो कोई स्वाभिमानी अधिकारी आना ही नहीं चाहता है और यदि ऐसे किसी अधिकारी की तैनाती हो भी गई तो वह महीने दो महीने से अधिक ठहरने नहीं दिया गया।

आज पलवल की हालत एक स्लम एरिया से भी बुरी है जहाँ गंदगी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जहाँ तक अधिकारियों के जनता के काम करने की बात है तो वह तो कोसो दूर है चारों तरफ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है।

पिछले कई वर्षों से पुलिस व्यवस्था का तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं हो। यहाँ दिन दहाड़े वारदात होना आम बात हो गई हैं। अब तो लोग पलवल को अपराधों के कारण उत्तरप्रदेश के जिले गाज़ियाबाद से भी ऊपर बताने लगे हैं। यहाँ की पुलिस स्वयं ही लूटपाट करती हर चौराहे पर खुलेआम देखी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले मुंडकटी चौकी पर गुडगाँव के एक प्रिंसिपल से एक हज़ार रुपये दिन दहाड़े कार चेकिंग के नाम पर लूट लिए थे जिसकी शिकायत उन्होंने डीजीपी से कर दी। इस पर उससे लूटे हुए पैसे तो वापिस कर दिए लेकिन करवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ सट्टा, अवैध शराब, ओवर लोड डंपर, पशु तश्कर पुलिस कमाई के सबसे बढ़िया साधन हैं। यहाँ से प्रतिदिन सैंकड़ों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गाय, भैंसों को लेकर उत्तर प्रदेश व दिल्ली जाती हैं। इन गाड़ियों में उनकी क्षमता से कई गुना तक पशु ठुंसे हुए होते हैं।

इस पशु तस्करी के कारण आये दिन यहाँ विवाद होते रहते हैं। पुलिस की इस कार्य प्रणाली के कारण इस क्षेत्र में हिन्दु-मेवों का भाईचारा तक भी बिगड़ रहा है। पलवल जिले में पशु तस्कारों ने गाँव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। ये तश्कर रात को तो छोडिये दिन दहाड़े ही लोगों के पशुओं को जबरन खोल ले जाते है। यहाँ से गौमांस रोजाना फरीदाबाद व दिल्ली तक पुलिस की मिलीभगत से जाता है। पिछले एस पी से उनके एक गाँव के दौरे के दौरान जब ग्रामीणों ने इस बारे शिकायत की थी तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से उलटे गाँव वालों को अपने पशुओं की अधिक सुरक्षा करने का सुझाव दे कर टाल दिया था।

यहाँ मेवाती लुटेरों ने तो अराजकता फैला रखी है। मेवाती लुटेरे कहीं भी किसी से भी कुछ भी लूट लेते हैं लेकिन पुलिस अधिकांश मामलों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है। एक उदाहरण ही इस लूट और पुलिस की बेबसी की पोल खोलने के लिए काफी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले हथीन के जन स्वास्थ्य विभाग की सरकारी गाड़ी को मेवाती लुटेरों ने उनके कार्यालय से ही उठा लिया एस डी ओ ने पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने की बजाय उन्हें सुझाव दिया कि गाड़ी को किसी तरह से भी किसी बिचौलियों के माध्यम से निकलवा लो अन्यथा गाड़ी कभी मिलेगी ही नहीं उलटे आप अपने विभाग के कानूनी झंझटों में फंस कर रह जाओगे। इस पर उनके विभाग के एक मेव कर्मचारी ने इस क्षेत्र के के प्रभावशाली छुटभैय्ये नेता जो इस तरह का काम करता के माध्यम से, जैसे-तैसे गाड़ी को निकलवाया।

ये बिचोलिये मेवात में आम हैं जो लोगों की चोरी की चीजों को फिरौती लेकर दिलवाने का धंधा करने का ही काम करते हैं। जो लोग थोड़े सयाने होते हैं वे पुलिस के पास जाने बजाय सीधे ही इन बिचौलियों के पास जाते हैं क्योंकि पलवल जिले भर में पुलिस किसी की रिपोर्ट दर्ज करती ही नहीं जब तक एक खास व्यक्ति या उसके परिवार का कोई आदमी पुलिस को न बोले। यहाँ बाइक सवार लुटेरों के द्वारा की जा रही वारदात तो अपनी चरम सीमा पर हैं। रोज अख़बारों में बाइक सवार लुटेरों द्वारा की गई वारदात की कोई न कोई कहानी छपती रहती हैं। पुलिस की हिम्मत ही नहीं है कि वो इस पर लगाम लगाये।

बाइक सवार गुंडे खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करते देखे जा सकते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड चला है बुलेट बाइक में मिस्त्रियों से उनके साइलन्सरों में बदलाव करवाकर ये गुंडे उनसे सड़क व गलियों में शोर मचाते फिरते हैं। यदि कहीं कोई लड़की पास से गुजर रही होती है उसके स्विच से भयंकर पटाखा कर देते हैं जिस से पास गुजरने वाला एकदम घबरा जाता है। अधिकतर बाइकों पर तो नंबर ही नहीं मिलेंगे जो कि अपराध का मुख्य कारण है।

ओवर लोड ट्रकों से भी पुलिस की काफी कमाई होती है। पुलिस के अतिरिक्त आरटीए भी इस कमाई में शामिल रहता है। पलवल में सट्टा पुलिस की कमाई का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ बड़े-बड़े सट्टेबाज हैं जिनके एरिया बटे हुए हैं।

पुलिस के ही सूत्रों से पता चला है कि पुलिस बाकायदा जुआ व सट्टा के एरिया का सख्ती से पालन करवाती है। शराब सप्लाई यहाँ गाँव व शहर में घर-घर होती है इस शराब तस्करी में तो काफी खून खराबा भी होता रहता। यह सब पुलिस की निगरानी में ही होता है। पलवल से रोजाना सैंकड़ो गाड़ियाँ नकली दूध, नकली पनीर व नकली खोवा आदि लेकर पलवल शहर, फरीदाबाद व दिल्ली सप्लाई करने जाती हैं लेकिन पुलिस की मंथली फिक्स होने के कारण ये ज़हर का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। अभी हाल में आये नए पुलिस कप्तान ने पलवल के चौराहों से कुछ अतिक्रमण तो हटवा दिया है लेकिन मथुरा रोड पर रसूलपुर चौक के पास तो पूरी सड़क को दोनों और से वर्षों से ट्रक वालों ने घेर कर रखा हुआ है। इस बारे में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब देखना है कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक यहाँ की कानून व्यवस्था में कितना सुधार लाते हैं और कितनी स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।